भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3669

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

छात्रों की कमी के कारण विद्यालयों का बंद होना

†3669. **श्री टी. आर. बालू:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में पर्याप्त संख्या में छात्रों की कमी के कारण बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान बंद किए गए विद्यालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ताकि छात्रों को पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोका जा सके?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना, बंद करना तथा युक्तिसंगत बनाना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) पर रिपोर्ट किए गए प्रारंभिक स्तर के सरकारी स्कूलों की कुल संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

यूडाइज+ पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्कूली शिक्षा के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सर्वसुलभ पहुंच में सुधार लाने की दिशा में प्रगति हुई है। यह वर्ष 2018-19 और 2025-26 के लिए सकल पहुंच अनुपात (जीएआर) से प्रमाणित होता हैः

वर्ष	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
2018-19	96.49	88.24	65.05
2025-26	98.14	95.05	94.79

जीएआरः सकल पहुँच अनुपात (जीएआर) किसी वर्ष में निर्धारित मानकों के अनुसार जिन गाँवों/बस्तियों में स्कूल उपलब्ध है, उनकी संख्या का उस वर्ष के कुल गाँवों/बस्तियों की संख्या से अनुपात है।

(ग): केंद्र सरकार, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत बालवाटिका से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराती है। सरकारी स्कूलों में ड्रॉपआउट को कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के नए स्कूल खोलना/उन्हें सुदृढ़ करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और उनका स्तरोन्नयन एवं संचालन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, सामयिक छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में कौशल शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और निःशुल्क यूनिफॉर्म, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

पीएम श्री योजना भी 14,500 से अधिक चयनित स्कूलों को अनुकरणीय स्कूलों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है जो एनईपी 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करते हुए पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हैं।

******

अनुलग्नक

'छात्रों की कमी के कारण विद्यालयों का बंद होना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री टी. आर. बालू द्वारा दिनांक 10/08/2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3669 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए प्रारंभिक स्तर के सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारत	प्रारंभिक स्तर के सरकारी स्कूल	
	2024-25	2025-26
भारत	889806	879940
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	234	234
आंध्र प्रदेश	37449	36003
अरुणाचल प्रदेश	2191	2097
असम	39807	39598
बिहार	66803	66915
चंडीगढ़	14	13
छत्तीसगढ़	43836	43853
दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव	299	291
दिल्ली	1546	1544
गोवा	686	677
गुजरात	32432	32398
हरियाणा	10869	10862
हिमाचल प्रदेश	11724	11465
जम्मू और कश्मीर	16196	16196
झारखंड	32704	32703
कर्नाटक	41967	41352
केरल	3498	3495
लद्दाख	681	599
लक्षद्वीप	25	23
मध्य प्रदेश	82726	81683
महाराष्ट्र	62793	62436
मणिपुर	2478	2457
मेघालय	7633	5459
मिजोरम	2227	2224
नागालैंड	1615	1588
ओडिशा	42555	42520
पुडुचेरी	280	280
पंजाब	15448	15443
राजस्थान	50288	49815
सिक्किम	636	606
तमिलनाडू	31288	31191
तेलंगाना	22983	21022
त्रिपुरा	3153	3095
उत्तर प्रदेश	134115	133948
उत्तराखंड	13619	13434
पश्चिम बंगाल	73008	72421

स्रोत: यूडाइज+